



करेंट अफेयर्स

छत्तीसगढ़

मई

2024

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009

Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501

Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

➤ दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने किया सरेंडर	3
➤ तदान प्रतिशत वृद्धि में स्वयं सहायता समूहों का योगदान	4
➤ PM-JAY का कार्यान्वयन	4
➤ SAIL-भिलाई द्वारा छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना	6
➤ छत्तीसगढ़ में तेंदुए का अवैध शिकार	6
➤ स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय फुटबॉल चैम्पियनशिप	8
➤ मुठभेड़ में मारा गया नक्सली	8
➤ स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय फुटबॉल चैम्पियनशिप	9
➤ छत्तीसगढ़ में खदान नीलामी	9
➤ छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग	11
➤ नक्सलियों के लिये पुनर्वास नीति	12
➤ बीजापुर में सात माओवादी मारे गए	12
➤ छत्तीसगढ़ में GST ई-वे बिल प्रावधान अनिवार्य	13
➤ यूरोशियन विम्ब्रेल	14

छत्तीसगढ़

दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने किया सरेंडर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा ज़िले में 35 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इन कैडरों को सड़कें खोदने, सड़कों को अवरुद्ध करने के लिये पेड़ काटने और नक्सलियों द्वारा बुलाए गए शटडाउन के दौरान पोस्टर तथा बैनर लगाने का कार्य सौंपा गया था।

मुख्य बिंदु:

- अधिकारियों के मुताबिक ये **नक्सली** दक्षिण बस्तर में माओवादियों की भैरमगढ़, मलांगेर और कटेकल्याण एरिया कमेटी का हिस्सा थे।
- ◆ वे पुलिस के पुनर्वास अभियान 'लोन वर्रातु' (घर वापस आइए) से प्रभावित थे और खोखली **माओवादी विचारधारा** से निराश थे।
 - **माओवाद माओ त्से तुंग** द्वारा विकसित साम्यवाद का एक रूप है। यह **सशस्त्र विद्रोह, जन लामबंदी और रणनीतिक गठबंधनों के संयोजन** के माध्यम से राज्य की सत्ता पर कब्जा करने का एक सिद्धांत है।
- इन नक्सलियों को **सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति** के तहत सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी।
- इसके साथ ही जून 2020 में शुरू किये गए पुलिस के **लोन वर्राटू अभियान** के तहत ज़िले में अब तक 180 इनामी समेत 796 नक्सली मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं।

लोन वर्राटू

- 'लोन वर्राटू' अभियान का अर्थ है 'घर वापस आइए'।
- यह अभियान उन नक्सलियों के लिये चलाया गया, जो **लाल आतंक** का रास्ता छोड़कर वापस **समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का इरादा रखते थे**।
- इस अभियान के तहत **कई नक्सलियों ने आतंक का रास्ता छोड़ा**।

नक्सलवाद

- **नक्सलवाद** शब्द का नाम पश्चिम बंगाल के गाँव नक्सलबाड़ी से लिया गया है।
- इसकी शुरुआत स्थानीय जमींदारों के खिलाफ विद्रोह के रूप में हुई, जिसने भूमि विवाद पर एक किसान की पिटाई की थी।
- यह आंदोलन जल्द ही पूर्वी भारत में छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्रप्रदेश जैसे राज्यों के कम विकसित क्षेत्रों में फैल गया।
- **वामपंथी उग्रवादी (LWE)** विश्व भर में माओवादियों और भारत में **नक्सली** के रूप में लोकप्रिय हैं।
- **उद्देश्य:**
 - ◆ वे **सशस्त्र क्रांति** के माध्यम से भारत सरकार को उखाड़ फेंकने और **माओवादी सिद्धांतों** पर आधारित एक **कम्युनिस्ट राज्य** की स्थापना का समर्थन करते हैं।
 - ◆ वे राज्य को **दमनकारी, शोषक और सत्तारूढ़** अभिजात वर्ग के हितों की सेवा करने वाले के रूप में देखते हैं, वे सशस्त्र संघर्ष एवं जनयुद्ध (People's War) के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक शिकायतों का समाधान करना चाहते हैं।

तदान प्रतिशत वृद्धि में स्वयं सहायता समूहों का योगदान

चर्चा में क्यों ?

लोकसभा चुनाव- 2024 के तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिये छत्तीसगढ़ के बलरामपुर ज़िले में एक पहल ध्यान आकर्षित कर रही है।

मुख्य बिंदु:

- महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं से मिलने, इमली के पत्ते और पीले चावल वितरित करने जैसे पारंपरिक तरीकों का प्रयोग कर मतदान में अधिक सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- इस प्रयास ने न केवल ग्रामीणों में उत्साह जगाया है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने में सामुदायिक भागीदारी की शक्ति का भी प्रदर्शन किया है।
- ◆ इस पहल को ज़िला प्रशासन का भी पूरा समर्थन प्राप्त है।

स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups - SHG)

- स्वयं सहायता समूह (SHG) उन लोगों के अनौपचारिक संघ हैं जो अपने जीवन स्तर में सुधार के तरीके खोजने के लिये एक साथ संगठित होते हैं।
- इसे समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले और सामूहिक रूप से एक सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के इच्छुक लोगों के स्व-शासित, सहकर्म-नियंत्रित सूचना समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
- स्व-रोज़गार और गरीबी उन्मूलन को प्रोत्साहित करने के लिये SHG "स्वयं सहायता" की धारणा पर निर्भर करता है।
- उद्देश्य:
 - ◆ रोज़गार और आय सृजन गतिविधियों के क्षेत्र में गरीबों तथा हाशिये पर मौजूद लोगों की कार्यात्मक क्षमता का निर्माण करना।
 - ◆ सामूहिक नेतृत्व एवं आपसी विचार-विमर्श के माध्यम से विवादों का समाधान करना।
 - ◆ बाज़ार संचालित दरों पर समूह द्वारा तय की गई शर्तों के साथ संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करना।
 - ◆ संगठित स्रोतों से उधार लेने का प्रस्ताव करने वाले सदस्यों के लिये सामूहिक गारंटी प्रणाली के रूप में कार्य करना।
 - गरीब अपनी बचत इकट्ठा करके बैंकों में जमा करते हैं। बदले में उन्हें अपना सूक्ष्म इकाई उद्यम शुरू करने के लिये कम ब्याज दर पर आसानी से ऋण प्राप्त होता है।

PM-JAY का कार्यान्वयन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में छत्तीसगढ़ में राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र के शोधकर्ताओं द्वारा किये गए एक अध्ययन में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) का खुलासा किया गया।

- PMJAY का उद्देश्य विशेष रूप से अस्पताल में रहने के दौरान जेब से होने वाले स्वास्थ्य खर्च को कम करना है।

मुख्य बिंदु:

- अध्ययन से पता चला है कि योजना में शामिल मरीजों को विशेष रूप से निजी अस्पतालों में अपनी जेब से अधिक खर्च वहन करना पड़ा, जिसका मुख्य कारण दोहरी बिलिंग जैसी सामान्य घटना थी।

- यह अध्ययन वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ में राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र के शोधकर्ताओं द्वारा 768 व्यक्तियों के साक्षात्कार के साथ संपन्न किया गया था, जिन्होंने साक्षात्कार से पहले अस्पताल में भर्ती होने के लिये PMJAY का उपयोग किया था। PMJAY ने राज्य में 1,006 सार्वजनिक और 546 निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया है।
- ◆ अध्ययन में पाया गया कि निजी अस्पतालों द्वारा योजना के अंतर्गत मरीजों से शुल्क लिया जा रहा है, जबकि PMJAY या आयुष्मान भारत के तहत ऐसा करना अनुचित है।
- ◆ फिर वे दोहरी बिलिंग में शामिल होकर उसी उपचार के लिये सरकार से प्रतिपूर्ति का दावा करेंगे जिसे धोखाधड़ी माना जाता है।
- निजी अस्पतालों के उपयोग को PMJAY के तहत गंभीर वित्तीय बोझ के लिये प्राथमिक कारक के रूप में पहचाना गया था।
- ◆ निजी अस्पतालों में लगभग 30% मामलों में ऐसे स्वास्थ्य व्यय (जो परिवार की बर्बादी का कारण बन जाते हैं) का आँकड़ा कुल वार्षिक गैर-चिकित्सा व्यय के 10% से अधिक हो गया।
- शोध से पता चला कि अनुसूचित जनजाति और महिलाओं जैसे हाशिये पर रहने वाले समूह PMJAY के माध्यम से निजी स्वास्थ्य देखभाल की पहुँच के बावजूद सार्वजनिक अस्पतालों पर बहुत अधिक निर्भर थे।
- ◆ इसमें बताया गया है कि सार्वजनिक अस्पतालों में इलाज कराने से व्यक्तियों को अपनी जेब से अधिक व्यय करने से बचने में सहायता मिलती है क्योंकि सार्वजनिक सेवाएँ निजी स्वास्थ्य देखभाल की तुलना में मरीजों के लिये काफी अधिक लागत प्रभावी होती हैं, भले ही वे सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित बीमा योजनाओं के अंतर्गत आती हों।
- ◆ भारत में निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के पास प्रभावी मूल्य और गुणवत्ता विनियमन का अभाव है, जिसके कारण निजी अस्पतालों द्वारा दोहरी बिलिंग को अपनाया जाता है जो रोगी देखभाल पर मुनाफे को प्राथमिकता देते हैं।
- ◆ अध्ययन में अस्पतालों के साथ अपने समझौतों में एक महत्वपूर्ण शर्त को लागू करने में सरकार की विफलता पर प्रकाश डाला गया, जो मरीजों से अतिरिक्त शुल्क लेने पर रोक लगाती है।

आयुष्मान भारत-PMJAY

- परिचय:
 - ◆ PM-JAY पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
 - ◆ इसे 2018 में लॉन्च किया गया, यह माध्यमिक देखभाल और तृतीयक देखभाल के लिये प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है।
 - स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, चिकित्सा और डे केयर उपचार, दवाओं व निदान की लागत शामिल है।
- लाभार्थी:
 - यह एक पात्रता आधारित योजना है जो नवीनतम सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) डेटा द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को लक्षित करती है।
 - राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को शेष (अप्रमाणित) SECC परिवारों की पहचान करने के लिये समान सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल वाले गैर-सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) के लाभार्थी परिवारों के डेटाबेस का उपयोग करने हेतु लचीलापन प्रदान किया है।
- वित्तीयन:
 - ◆ इस योजना का वित्तपोषण संयुक्त रूप से किया जाता है, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मामले में केंद्र एवं विधायिका के बीच 60:40, पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड के लिये 90:10 और विधायिका के बिना केंद्रशासित प्रदेशों हेतु 100% केंद्रीय वित्तपोषण का प्रावधान है।

- केंद्रक अभिकरण:
 - ◆ राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health Authority- NHA) को राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से PMJAY के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में गठित किया गया है।
 - ◆ राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) राज्य में ABPMJAY के कार्यान्वयन के लिये जिम्मेदार राज्य सरकार की शीर्ष निकाय है

SAIL-भिलाई द्वारा छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना

चर्चा में क्यों ?

राज्य संचालित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) की छत्तीसगढ़ स्थित शाखा, भिलाई स्टील प्लांट (BSP), कार्बन फुटप्रिंट में सुधार के लिये अपने मरोदा-1 जलाशय में राज्य की पहली 15-मेगावाट (MW) फ्लोटिंग सौर परियोजना स्थापित करेगी।

- इस्पात प्रमुख कंपनी कार्बन उत्सर्जन को कम करने, ऊर्जा संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न परियोजनाएँ चला रही है।

मुख्य बिंदु:

- यह परियोजना NTPC-SAIL पावर सप्लाय कंपनी लिमिटेड (NSPCL) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है, जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (NTPC) और SAIL की एक 50:50 साझेदारी वाली संयुक्त उद्यम कंपनी है। सोलर प्लांट दुर्ग जिले में स्थापित किया जाएगा।
- मरोदा जलाशय का क्षेत्रफल 2.1 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जल भंडारण क्षमता 19 घन मिलीमीटर (MM³) है।
 - ◆ मरोदा-I जलाशय में संग्रहीत जल न केवल संयंत्र को बल्कि टाउनशिप को भी जल आपूर्ति करता है।
- इस संयंत्र से अनुमानित कुल हरित विद्युत ऊर्जा उत्पादन लगभग 34.26 मिलियन यूनिट सालाना होने की संभावना है।
 - ◆ इस परियोजना से BSP के CO₂ उत्सर्जन में सालाना 28,330 टन की कमी आने की उम्मीद है।

कार्बन फुटप्रिंट

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) के अनुसार, कार्बन फुटप्रिंट जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) की मात्रा पर लोगों की गतिविधियों के प्रभाव का एक माप है और इसे कई टन में उत्पादित CO₂ उत्सर्जन के भार के रूप में व्यक्त किया जाता है।
- इसे आमतौर पर प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले कई टन CO₂ के रूप में एक संख्या में (जिसे मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों सहित कई टन CO₂-समतुल्य गैसों द्वारा पूरक किया जा सकता है) मापा जाता है।
- यह एक व्यापक उपाय हो सकता है या किसी व्यक्ति, परिवार, घटना, संगठन या यहाँ तक कि पूरे देश के कार्यों पर लागू किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ में तेंदुए का अवैध शिकार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कटघोरा वनमंडल के अंतर्गत चैतमा वन परिक्षेत्र में लगभग सात वर्ष के तेंदुए का शव मिला था।

मुख्य बिंदु:

- अधिकारियों के अनुसार तेंदुए के शरीर के कुछ अंग गायब थे जिससे अवैध शिकार की अटकलें लगाई जा रही थीं।

- सींग, दाँत, खाल या हड्डियों जैसे वांछनीय शरीर के अंगों को बेचने के उद्देश्य से प्रायः वन्यजीवों का अवैध शिकार, आखेट या हत्या कर दी जाती है।
- ◆ भारत के वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) और संलग्न पुलिस अधिकारियों से उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, देश में वर्ष 2012 और 2018 के दौरान 9,253 से अधिक शिकारियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सजा की दर सिर्फ 2% थी।
- अवैध वन्यजीव व्यापार उच्च लाभ मार्जिन और यहाँ तक कि कई मामलों में दुर्लभ प्रजातियों के लिये चुकाई जाने वाली ऊँची कीमतों से प्रेरित होते हैं।
- जब प्रकृति में मानव उपभोग की दर को बनाए रखने के लिये प्राकृतिक भंडार का पुनर्भरण नहीं हो पाता है तो कमजोर वन्य जीव विलुप्ति की कगार पर चले जाते हैं।
- वन्य जीवों का अवैध शिकार विशेष रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, उत्तराखंड और असम राज्यों में प्रचलित है।

तेंदुए



- वैज्ञानिक नाम: पेंथेरा पार्डस (*Panthera pardus*)
- परिचय:
 - ◆ पेंथेरा जीनस के सबसे छोटे सदस्य के रूप में बाघ, शेर (पेंथेरा लियो), जगुआर, तेंदुए तथा हिम तेंदुए आदि शामिल हैं, तेंदुए विभिन्न प्रकार के वातावरणों के लिये अपनी अनुकूलन क्षमता के लिये प्रसिद्ध है।
 - ◆ यह एक रात्रिचर जानवर है जो रात में शिकार करता है।
 - ◆ यह जंगली सूअर, हॉग हिरण एवं चीतल सहित अपने क्षेत्र में छोटे शाकाहारी जानवरों को खाता है।

- ◆ तेंदुओं में मेलेनिज्म एक आम घटना है, जिसमें जानवर की पूरी त्वचा काले रंग की होती है, जिसमें उसके धब्बे भी शामिल हैं।
- ◆ मेलेनिस्टिक तेंदुए को प्रायः **ब्लैक पेंथर** कहा जाता है और गलती से इसे एक अलग प्रजाति मान लिया जाता है।
- **प्राकृतिक आवास:**
 - ◆ यह उप-सहारा अफ्रीका में पश्चिमी और मध्य एशिया के छोटे हिस्सों एवं भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर दक्षिण-पूर्व तथा पूर्वी एशिया तक विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है।
 - ◆ भारतीय तेंदुआ (**पेंथेरा पार्डस फुस्का**) भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक रूप से पाया जाने वाला तेंदुआ है।

स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय फुटबॉल चैम्पियनशिप

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **स्वामी विवेकानंद** अंडर-20 पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल चैम्पियनशिप क्वार्टर फाइनल रामकृष्ण मिशन आश्रम ग्राउंड, नारायणपुर, छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया था।

मुख्य बिंदु:

- असम फुटबॉल चैम्पियनशिप के क्वार्टर फाइनल में मिज़ोरम से हार गया। चैम्पियनशिप में कुल 32 राज्यों ने भाग लिया।
- अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (**All India Football Federation- AIFF**) ने अप्रैल 2024 में स्वामी विवेकानंद U20 राष्ट्रीय फुटबॉल चैम्पियनशिप की घोषणा की।
- ◆ नई शुरू की गई U20 चैम्पियनशिप के अलावा, AIFF दो अन्य पुरुष आयु वर्ग प्रतियोगिताएँ, जूनियर NFC और सब-जूनियर NFC भी आयोजित करता है।

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (All India Football Federation- AIFF)

- अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) भारत में फुटबॉल खेल के प्रबंधन से संबंधित संगठन है।
- यह भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के संचालन का प्रबंधन करता है और कई अन्य प्रतियोगिताओं तथा टीमों के अलावा भारत की प्रमुख घरेलू क्लब प्रतियोगिता I-लीग को भी नियंत्रित करता है।
- AIFF की स्थापना वर्ष 1937 में हुई थी और वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1948 में फीफा की संबद्धता प्राप्त की थी।
- वर्तमान में इसका कार्यालय द्वारका, नई दिल्ली में है। भारत में यह वर्ष 1954 में एशियाई फुटबॉल परिषद के संस्थापक सदस्यों में से एक था।

मुठभेड़ में मारा गया नक्सली

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले में सुरक्षाकर्मियों के साथ गोलीबारी में एक **नक्सली** मारा गया।

मुख्य बिंदु:

- गोलीबारी सुबह टोलनाई और तेतराई गाँवों के बीच एक वन क्षेत्र के पहाड़ी में हुई जब सुरक्षाकर्मियों की एक टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी।
- इस घटना के साथ ही वर्ष 2024 में अब तक छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ अलग-अलग मुठभेड़ों में 105 नक्सली मारे जा चुके हैं।

भारत में नक्सलवाद:

- भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग ज़िले के नक्सलबाड़ी नामक गाँव से हुई और इसीलिये इस उग्रपंथी आंदोलन को 'नक्सलवाद' के नाम से जाना जाता है।

- इसकी शुरुआत स्थानीय जमींदारों के खिलाफ विद्रोह के रूप में हुई, जिन्होंने भूमि विवाद पर एक किसान की पिटाई की थी। विद्रोह की शुरुआत वर्ष 1967 में **कानू सान्याल और जगन संथाल** के नेतृत्व में मेहनतकश किसानों को भूमि के उचित पुनर्वितरण के उद्देश्य से की गई थी
- पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ यह आंदोलन पूरे पूर्वी भारत: छत्तीसगढ़, ओडिशा के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के कम विकसित क्षेत्रों में भी फैल गया है।
- यह माना जाता है कि नक्सली **माओवादी राजनीतिक भावनाओं** और विचारधारा का समर्थन करते हैं।
- ◆ **माओवाद**, साम्यवाद का एक रूप है जो माओ त्से तुंग द्वारा विकसित किया गया है। इस सिद्धांत के समर्थक सशस्त्र विद्रोह, जनसमूह और रणनीतिक गठजोड़ के संयोजन से राज्य की सत्ता पर कब्जा करने में विश्वास रखते हैं।

स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय फुटबॉल चैम्पियनशिप

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **स्वामी विवेकानंद अंडर-20 पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल चैम्पियनशिप क्वार्टर फाइनल** रामकृष्ण मिशन आश्रम ग्राउंड, नारायणपुर, छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया था।

मुख्य बिंदु:

- असम फुटबॉल चैम्पियनशिप के **क्वार्टर फाइनल में मिज़ोरम से हार** गया। चैम्पियनशिप में **कुल 32 राज्यों ने भाग** लिया।
- **अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (All India Football Federation- AIFF)** ने अप्रैल 2024 में स्वामी विवेकानंद U20 राष्ट्रीय फुटबॉल चैम्पियनशिप की घोषणा की।
- ◆ नई शुरु की गई U20 चैम्पियनशिप के अलावा, AIFF दो अन्य पुरुष आयु वर्ग प्रतियोगिताएँ, जूनियर NFC और सब-जूनियर NFC भी आयोजित करता है।

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (All India Football Federation- AIFF)

- अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) भारत में **फुटबॉल खेल के प्रबंधन से संबंधित संगठन** है।
- यह भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के संचालन का प्रबंधन करता है और कई अन्य प्रतियोगिताओं तथा टीमों के अलावा भारत की प्रमुख घरेलू क्लब प्रतियोगिता I-लीग को भी नियंत्रित करता है।
- AIFF की **स्थापना वर्ष 1937 में हुई थी** और वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1948 में फीफा की संबद्धता प्राप्त की थी।
- वर्तमान में इसका कार्यालय **द्वारका, नई दिल्ली** में है। भारत में यह वर्ष 1954 में एशियाई फुटबॉल परिसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक था।

छत्तीसगढ़ में खदान नीलामी

चर्चा में क्यों ?

छत्तीसगढ़ के **कोरबा ज़िले** में **लिथियम खदान**, जिसमें लोकसभा चुनाव के कारण देरी हुई थी, की आगामी महीने में नीलामी की उम्मीद है।

मुख्य बिंदु:

- मार्च 2024 में, खान मंत्रालय ने नीलामी के लिये एक निविदा जारी की थी, जिसमें **कोल इंडिया (CIL)** जैसी कई कंपनियों ने अपनी रुचि व्यक्त की थी।

- अधिकारियों के मुताबिक चुनाव आचार संहिता के कारण निविदा जारी नहीं जा सकीं और मंत्रालय जल्द ही प्रक्रिया शुरू करेगा।
- फरवरी 2023 में, **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI)** ने कटघोरा तहसील में लिथियम की खोज की। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, लिथियम भंडार 256.12 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसमें 84.86 हेक्टेयर वन क्षेत्र भी शामिल है।
- जियोकेमिकल मैपिंग से **कटघोरा क्षेत्र** में सात मिश्रित नमूनों में लिथियम के असंगत मूल्य सामने आए। ये 82.606 और 155 भाग प्रति मिलियन के बीच थे।

लिथियम

- **परिचय:**
 - ◆ लिथियम (Li), जिसे कभी-कभी रिचार्जबल बैटरी के लिये उच्च मांग के कारण 'सफेद सोना' भी कहा जाता है, एक नरम और चाँदी जैसी श्वेत धातु है।
- **निष्कर्षण:**
 - ◆ भंडार के प्रकार के आधार पर लिथियम का अलग-अलग तरीकों से निष्कर्षण किया जा सकता है- आम तौर पर या तो **बड़े ब्राइन पूलों के सौर वाष्पीकरण** के माध्यम से, या **अयस्क के हार्ड-रॉक निष्कर्षण** से।
- **प्रयोग:**
 - ◆ लिथियम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल (EV), लैपटॉप, मोबाइल आदि की बैटरी में प्रयोग किये जाने वाले **इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक महत्वपूर्ण घटक** है।
 - ◆ इसका प्रयोग **थर्मो-न्यूक्लियर अभिक्रियाओं** में भी किया जाता है।
 - ◆ इसका प्रयोग एल्यूमीनियम और मैग्नीशियम के साथ **मिश्र धातु बनाने**, उनकी कठोरता में सुधार करने एवं उन्हें हल्का बनाने के लिये किया जाता है।
 - **मैग्नीशियम-लिथियम मिश्र धातु**- कवच प्लेट के लिये।
 - **एल्यूमीनियम-लिथियम मिश्र धातु**- विमान, साइकिल फ्रेम और हाई-स्पीड ट्रेनों में।
- **प्रमुख वैश्विक लिथियम भंडार:**
 - ◆ चिली > ऑस्ट्रेलिया > अर्जेंटीना लिथियम भंडार वाले शीर्ष देश हैं।
 - ◆ लिथियम ट्रायंगल: चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया।
- **भारत में लिथियम भंडार:**
 - ◆ प्रारंभिक सर्वेक्षण में **दक्षिणी कर्नाटक के मांड्या ज़िले** में सर्वेक्षण की गई भूमि के एक छोटे से हिस्से में 14,100 टन का अनुमानित लिथियम भंडार दिखाया गया है।
- **अन्य संभावित साइटें:**
 - ◆ राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश में अभ्रक बेल्ट।
 - ◆ ओडिशा और छत्तीसगढ़ में पेगमैटाइट बेल्ट।
 - ◆ गुजरात में कच्छ का

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण:

- वर्तमान में GSI **खान मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय** है। इसकी स्थापना वर्ष 1851 में मुख्य रूप से रेलवे के लिये **कोयला भंडार खोजने हेतु** की गई थी।
- समय के साथ यह भू-विज्ञान सूचना के भंडार के रूप में विकसित हुआ है और **अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के भू-वैज्ञानिक संगठन का दर्जा भी प्राप्त किया है।**

- इसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसके छह क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलॉन्ग तथा कोलकाता में स्थित हैं। प्रत्येक राज्य की एक राज्य इकाई होती है।
- केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड (Central Geological Programming Board- CGPB) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का एक महत्वपूर्ण मंच है जो संपर्क हेतु सुविधा प्रदान करता है और कार्य के दोहराव से बचाता है।

छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग

चर्चा में क्यों ?

छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ (CSCS) पहली बार छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग (CCPL) T20 टूर्नामेंट की मेजबानी के लिये तैयारी कर रहा है।

मुख्य बिंदु:

- यह आयोजन 7 से 16 जून तक नया रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा।
- इसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा मंजूरी दे दी गई है।
- ◆ CCPL में छह टीमें रायगढ़ लायंस, रायपुर राइनो, राजनांदगाँव पैंथर्स, बिलासपुर बुल्स, सरगुजा टाइगर्स और बस्तर बाइसन शामिल होंगी।
- पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को CCPL का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया है।
- छत्तीसगढ़ के कई उभरते सितारों को अपना कौशल दिखाने और चयनकर्ताओं को प्रभावित करने का मौका मिलेगा।



(L to R) Ashutosh Singh, Amandeep Khare, Suresh Raina, Ajay Mandal, Shubham Agrawal, Shashank Chandrakar

Bilaspur Bulls SHASHANK SINGH	Raigarh Lions SHUBHAM AGRAWAL	Surguja Tigers ASHUTOSH SINGH	TOTAL MATCHES 18
Raipur Rhinos AMANDEEP KHARE	Rajnandgaon Panthers AJAY MANDAL	Bastar Bisons SHASHANK CHANDRAKAR	

■ Team ■ Captain

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI)

- यह भारत में क्रिकेट की राष्ट्रीय शासी निकाय है।
- इसका मुख्यालय मुंबई के चर्चगेट में क्रिकेट सेंटर में स्थित है।
- इसे तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1975 के तहत पुनः पंजीकृत किया गया था।

नक्सलियों के लिये पुनर्वास नीति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री ने नक्सलियों से मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की थी और आत्मसमर्पण करने पर नई पुनर्वास नीति के लिये उनसे सुझाव मांगे थे।

मुख्य बिंदु:

- डिप्टी सीएम के मुताबिक, माओवादियों से बातचीत के लिये सभी रास्ते खुले हैं। राज्य सरकार ने नियद नेल्लानार योजना के तहत गाँवों में सड़क, स्वास्थ्य सेवाएँ, जल और अन्य सुविधाएँ प्रदान करके समानता तथा विकास का माहौल बनाया है।
- ◆ नक्सल विरोधी अभियान और मुठभेड़ नक्सल प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के राज्य सरकार के प्रयासों का एक छोटा-सा हिस्सा थे।

नियद नेल्लानार योजना

- नियद नेल्लानार, जिसका अर्थ है "आपका अच्छा गाँव" या "घोर गुड विलेज" स्थानीय दंडामी बोली (दक्षिण बस्तर में बोली जाने वाली) है।
- इस योजना के तहत बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा शिविरों के 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित गाँवों में सुविधाएँ और लाभ प्रदान किये जाएंगे।
- ◆ बस्तर में 14 नये सुरक्षा कैम्प स्थापित किये गए हैं। ये शिविर नई योजना के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने में भी सहायता करेंगे। नियद नेल्लानार के तहत ऐसे गाँवों में लगभग 25 बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी

बीजापुर में सात माओवादी मारे गए

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और बीजापुर जिलों के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में सात माओवादी मारे गए।

मुख्य बिंदु:

- यह मुठभेड़ दंतेवाड़ा के बारसूर पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में अबूझमाड़ वन क्षेत्र से सिर्फ 10 किलोमीटर अंदर हुई।
- सुरक्षा बलों में विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की टीमों के साथ बस्तर फाइटर्स और जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) शामिल थे।
- इस ऑपरेशन में लगभग 1,000 कर्मियों की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) के साथ नारायणपुर और बस्तर जिलों के जिला रिजर्व गार्ड, बस्तर फाइटर्स और छत्तीसगढ़ पुलिस की सभी इकाइयाँ शामिल थीं

भारत में नक्सलवाद:

- भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी नामक गाँव से हुई और इस उग्रपंथी आंदोलन को 'नक्सलवाद' के नाम से जाना जाता है।

- इसकी शुरुआत स्थानीय जमींदारों, जिन्होंने भूमि विवाद के चलते एक किसान की पिटाई कर दी थी, के खिलाफ विद्रोह के रूप में हुई। विद्रोह की शुरुआत वर्ष 1967 में कानू सान्याल और जगन संधाल के नेतृत्व में मेहनतकश किसानों को भूमि के उचित पुनर्वितरण के उद्देश्य से की गई थी।
- पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ यह आंदोलन पूरे पूर्वी भारत: छत्तीसगढ़, ओडिशा के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के कम विकसित क्षेत्रों में भी फैल गया।
- यह माना जाता है कि नक्सली माओवादी राजनीतिक भावनाओं और विचारधारा का समर्थन करते हैं।
- ◆ माओवाद, साम्यवाद का एक रूप है जो माओ त्से तुंग द्वारा विकसित किया गया है। इस सिद्धांत के समर्थक सशस्त्र विद्रोह, जनसमूह और रणनीतिक गठजोड़ के संयोजन से राज्य की सत्ता पर कब्जा करने में विश्वास रखते हैं।

छत्तीसगढ़ में GST ई-वे बिल प्रावधान अनिवार्य

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर 50,000 रुपए से अधिक मूल्य के सभी अंतर्राज्यीय माल परिवहन हेतु ई-वे बिल बनाना अनिवार्य कर दिया है, जिससे कुछ वस्तुओं के लिये पहले दी गई छूट समाप्त हो गई है।

- ई-वे बिल एक अनुपालन प्रणाली है, जिसमें डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से माल की आवाजाही करने वाला व्यक्ति माल की आवाजाही शुरू होने से पहले प्रासंगिक जानकारी अपलोड करता है और वस्तु एवं सेवा कर (GST) पोर्टल पर ई-वे बिल तैयार करता है।

मुख्य बिंदु:

- प्रारंभ में, जिलों के भीतर विशिष्ट वस्तुओं की आवाजाही को सरल बनाने के लिये अपवाद दिये गए थे, लेकिन अनुपालन में सुधार लाने तथा धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहारों में कमी लाने हेतु इन्हें वापस ले लिया गया है।
- नीति में यह बदलाव ई-वे बिल प्रणाली के साथ समायोजन के छह वर्ष बाद आया है, जिसे शुरू में वर्ष 2018 में लागू किया गया था। प्रणाली के अभ्यस्त होने की अवधि ने व्यवसायों और ट्रांसपोर्टों को इससे परिचित होने का मौका दिया है, जिससे छूट समाप्त हो गई है।
- इन छूटों को समाप्त करने का उद्देश्य सर्कुलर ट्रेडिंग और फर्जी बिलिंग जैसी समस्याओं का समाधान करना है, जो पिछली रियायतों का लाभ उठा रहे हैं।
- इसका लक्ष्य निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, ITC संग्रह को बढ़ाना और वैध व्यवसायों के लिये समान अवसर उपलब्ध कराना है।

इलेक्ट्रॉनिक वे (ई-वे) बिल

- इलेक्ट्रॉनिक वे बिल या 'ई-वे बिल' प्रणाली GST व्यवस्था में 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक 50,000 रुपए से अधिक मूल्य की वस्तु की अंतर्राज्यीय और अंतः राज्यीय आवाजाही को ट्रैक करने के लिये तकनीकी ढाँचा प्रदान करती है।
- जब ई-वे बिल तैयार किया जाता है, तो एक अद्वितीय ई-वे बिल नंबर (EBN) आवंटित किया जाता है तथा यह आपूर्तिकर्ता, प्राप्तकर्ता और ट्रांसपोर्ट के लिये उपलब्ध होता है।
- इसे निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु लॉन्च किया:
 - ◆ वस्तु की तीव्र आवाजाही को सुगम बनाना।
 - ◆ वाहनों के टर्नअराउंड समय में सुधार करना।
 - ◆ यात्रा की औसत दूरी बढ़ाकर और यात्रा के समय के साथ-साथ लागत को कम करके लॉजिस्टिक्स उद्योग की सहायता करना।

यूरेशियन विम्ब्रेल

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में ग्लोबल पोज़िशनिंग सिस्टम (GPS) ट्रांसमीटर से टैग किये गए एक प्रवासी पक्षी 'यूरेशियन या कॉमन विम्ब्रेल' को पहली बार कैमरे में रिकॉर्ड किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- पक्षी विज्ञानियों और राज्य वन अधिकारियों के अनुसार, प्रवासी पक्षी लंबी दूरी से प्रवास करते हुए छत्तीसगढ़ में देखे गए, क्योंकि रायपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर बेमेतरा ज़िले के बेरला क्षेत्र में आर्द्रभूमि मौजूद है।
- भारत में यह पहली बार है कि इस तरह के जीपीएस-टैग वाले पक्षी को देखा गया।
- वनस्पति के नुकसान और अतिक्रमण का सामना कर रहे ऐसे जलीय जैवविविधता वाले आवास तथा आर्द्रभूमि को बहाल करने की अधिक आवश्यकता है।

यूरेशियन विम्ब्रेल



- यह स्कोलोपेसिडे परिवार का एक दलदली पक्षी है।
- वैज्ञानिक नाम: न्यूमेनियस फेओपस

- क्षेत्र:
 - ◆ यह पाँच महाद्वीपों में फैले हुए हैं: उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और यूरोप।
 - ◆ वे गर्मियों के महीनों में साइबेरिया और अलास्का के उप-आर्कटिक क्षेत्रों में प्रजनन करते हैं तथा फिर दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका एवं नेपाल सहित दक्षिण एशिया के शीतकालीन क्षेत्रों में प्रवास करते हैं।
- आवास: शीतकाल में मुख्यतः समुद्र तट, आर्द्रभूमि, मैंग्रोव, दलदली भूमि और बड़ी नदियों के तट पर निवास करते हैं।
- विशेषताएँ:
 - ◆ यह काफी बड़ा भूरा-भूरा पक्षी है, जिसकी लंबी घुमावदार चोंच होती है।
 - ◆ इसके सिर की संरचना अलग है, जिसमें गहरे रंग की धारीदार आँखें हैं।
 - ◆ यह ऊपर से गहरे भूरे रंग का और नीचे से हल्का पीला होता है तथा गले एवं छाती पर बहुत अधिक भूरे रंग की धारियाँ होती हैं।
 - ◆ विम्ब्रेल अपनी ऊँची आवाज़ के लिये जाने जाते हैं, जिसमें सात स्वरों की एक दोहरावदार श्रृंखला होती है।
- संरक्षण की स्थिति:
 - ◆ **IUCN रेड लिस्ट:** बहुत कम संकट (Least Concern)

◆ ◆ ◆ ◆

दृष्टि
The Vision